हटा नियंत्रण, थोक में चढ़े चीनी के भाव

चीनी की कीमतों में शुक्रवार को 30 से 40 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के बाद चीनी के दाम चढ़ने लगे हैं। आज चीनी की कीमतों में 30 से 40 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। कारोबारियों के मुताबिक इस माह चीनी 100 से 150 रुपये महंगी हो सकती है। जानकार बताते हैं कि चालू चीनी वर्ष में सप्लाई के दबाव और कुछ समय तक सरकार की कड़ी नजर रहने से भले ही भारी तेजी न आए, लेकिन अगले चीनी वर्ष में दाम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर जा सकते हैं। गुरुवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने चीनी उद्योग को सशर्त नियंत्रण मुक्त करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब खुले बाजार में बिक्री के लिए कोटा और राशन की दुकानों के लिए लेवी चीनी की व्यवस्था खत्म हो गई है।

चीनी कारोबारी आर पी गर्ग ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकारी नियंत्रण की वजह से चीनी के दाम लागत से भी नीचे चल रहे थे। गुरुवार को इस उद्योग से सरकारी बंदिशें हटने के बाद आज दिल्ली में चीनी के भाव 40 रुपये बढ़कर 3230-3340 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक्स फैक्टरी भाव में भी तेजी दर्ज की गई। चीनी विक्रेता कंपनी एसएनबी इंटरप्राइजेज के सुधीर भालोटिया ने कहा कि इस फैसले के बाद दाम बढ़ना लाजिमी है। कमोडिटी इनसाइट डॉट कॉम के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक प्रशांत कपूर का कहना है कि लेवी कोटा खत्म होने से चीनी मिलों को नुकसान से राहत मिलेगी। दूसरी ओर अब मिलों पर बाजार में चीनी आपूर्ति का दबाव नहीं रहेगा। यानी दाम सुस्त होने पर मिलें आपूर्ति घटाकर कीमतें बढ़वा सकती हैं। उनका अनुमान है कि इस माह चीनी 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हो सकती है। इंडियाबुल्स कमोडिटी के सह उपाध्यक्ष (शोध) बदरुद्दीन की राय में लंबी अवधि में चीनी के दाम बढ़ेंगे।

कीमतों में आएगी तेजी

- इस महीने 100 से 150 रुपये महंगी हो सकती है चीनी
- अगले चीनी वर्ष के दौरान चीनी के दाम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से जा सकते हैं ऊपर
- लेवी कोटा खत्म होने से मिलों को नहीं होगा नुकसान
- अब मिलों पर बाजार में आपूर्ति का दबाव नहीं रहेगा

चीनी मिलों का हुआ मुंह मीठा

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 5 अप्रैल

सरकार के चीनी उद्योग को आंशिक रुप से विनियंत्रित करने के फैसले से चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी मिलों का औसत शुद्ध लाभ 3 फीसदी बढ़ेगा। सरकार ने 10 फीसदी लेवी चीनी प्रणाली समाप्त करने और राशन प्रणाली के जरिये सस्ती दरों पर चीनी बेचने के लिए खुले बाजार से खरीद करने का फैसला लिया है। इससे मिलों को 10 फीसदी अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है। लेवी प्रणाली के तहत मिलों को चीनी उत्पादन का 10 फीसदी हिस्सा सरकार को 19 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना होता था, जबकि चीनी की वर्तमान कीमतें 28-29 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, जो उत्पादन लागत के समान ही हैं। इससे सरकार को दी जा रही चीनी पर मिलों को 10-11 रुपये प्रति किलोग्राम का नुकसान हो रहा था। सरकार इस चीनी की बिक्री राशन प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को करती है।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक सिंभावली शुगर इंडस्ट्रीज के मुख्य वित्त अधिकारी संजय तापड़िया ने कहा, 'यह हमारे वार्षिक लाभ में जुड़ने वाली अतिरिक्त आमदनी होगी।' चीनी मिलों ने इस साल आवश्यक लेवी चीनी प्रणाली के तहत बिल्कुल भी चीनी नहीं बेची है।

शीर्ष कारोबारी संस्था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने स्टॉक में कमी और बेहतर नकदी प्रवाह के अलावा उद्योग को 3,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होने का अनुमान लगाया है। बलरामपुर चीनी के मुख्य वित्त अधिकारी किशोर शाह ने कहा, 'करीब 3 फीसदी अतिरिक्त नकदी आने से उद्योग उस पर बकाया का भुगतान कर सकेगा।' इस बीच चीनी कंपनियों के शेयर शुरुआती कारोबार में 20 फीसदी तक चढ़ गए। बजाज हिंदुस्तान, श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, मवाना शुगर्स, अवध शुगर्स और धामपुर शुगर मिल्स के शेयरों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर तेजी के साथ कारोबार हुआ।

बिजनेस स्टैंडर्ड
6/4/13